Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्रबंधकीय शिक्षा का रोजगार के अवसरों में योगदान

डॉ. अधिकेश राय* श्रीमती अन्नपूर्णिमा कोष्टा**

*** शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत**
**** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) ठाकुर निरंजन सिंह शासकीय महाविद्यालय, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व नैतिक शक्तियों का विकास करती है और उसे स्वस्थ्य एवं सुखी जीवन व्यतीत करने की कुंजी प्रदान करती है। पूर्व में उच्च शिक्षा प्राप्ति की अभिलाषा समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने तक ही सीमित थी। किन्तु वर्तमान युग में उच्च प्रबंधकीय व व्यावसायिक शिक्षा प्राप्ति की अभिलाषा समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति अपने लिए उच्च शिक्षा की उपयुक्त शाखा व विषयों का चुनाव केवल अपनी अभिरूचि व योग्यता के आधार पर नहीं करता है बल्कि उसको रोजगार प्रदान करने वाली क्षमता व स्वरोजगार की संभावना पर भी विचार करता है। शिक्षा के संबंध में यही विचार प्रबंधकीय शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित करता है। भारतीय समाज विविधतापूर्ण समाज है। यह सांस्कृतिक, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक रूप से बदल रहा है और शिक्षा इन परिवर्तनों से प्रभावित है। चूंकि शिक्षा से मनुष्य को ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्य और कौशल प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए शिक्षा को और अधिक गतिशील एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

शब्द कुंजी – प्रबंधकीय व व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, आर्थिक विकास।

प्रस्तावना – भारत में वैदिक सभ्यताकाल से गुरूकुल पद्धति के रूप में विकसित शिक्षा प्रणाली में जहां एक ओर जीवन के लिए आवश्यक शिक्षा प्रदान की जाती थी, वहीं दूसरी ओर योग्यता आधारित रोजगारोन्मुखी आधारभूत शिक्षा अर्थात् व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। यह शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को इस योग्य बनाती थी कि वह स्वयं के अलावा परिवार, समाज एवं देश की समृद्धि में पर्याप्त योगदान कर सकता था। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् निरक्षर, निर्धन और अविकसित भारत के विकास हेतु महात्मा गांधी जैसे अर्थवेत्ताओं एवं शिक्षाविदों ने स्वावलंबन आधारित व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर बल दिया परन्तु डिग्री आधारित सैद्धांतिक शिक्षा का विकास ही हावी रहा। जिससे स्वरोजगार विकास एक तरह से अवरूद्ध हुआ और रोजगार के अवसर कम उत्पन्न हुए। फलस्वरूप डिग्री धारकों / शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। वर्ष 1987-88 से सम्पूर्ण देश में व्यावसायिक शिक्षा का क्रियान्वयन हुआ जिसका उद्देश्य 'राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि एवं व्यक्तिगत समृद्धि हेतु शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना तथा कुशल मानव शक्ति की मांग एवं पूर्ति के बीच व्याप्त विषमता को कम करना है।'

मध्यप्रदेश में प्रबंधकीय शिक्षा का स्वरूप – वर्तमान समय के बदलते परिवेश में शिक्षा का स्वरूप एवं उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना या समझ विकसित करना नहीं है, वरन् शिक्षा नौकरी प्राप्त करने का एक साधन मात्र बनकर रह गई है। प्रत्येक विद्यार्थी यह मानकर स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेता है कि बी.ए. या एम.ए. उपाधि प्राप्त करने के बाद वह किसी शासकीय सेवा में जाने योग्य हो जायेगा। आज का विद्यार्थी नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा के स्थान पर केवल उपाधि प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह एक सीमित पाठ्यक्रम में बंधकर उपाधि प्राप्त करता है एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य से भटकता जा रहा है। यदि वर्तमान संदर्भ में देखा जाये तो शिक्षा का स्वरूप पहले से अधिक व्यापक रूप में सामने आ रहा है।

साहित्य शिक्षा के साथ यदि कला कौशल का भी सम्मिश्रण रखा जाये और स्नातकों को किसी शिल्प का ज्ञान करा दिया जाये तो आर्थिक समस्याओं का सहज ही समाधान हो सकता है। आज के भौतिकवादी युग में प्रत्येक परिस्थिति से लड़ने के लिए हमारे नवयुवक तैयार हैं। इसके लिए आवश्यकता है उनमें क्षमता उत्पन्न करनी की। हमारा लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जब हमारी शिक्षा इसके अनुकूल होगी अर्थात् शिक्षा की महिमामयी शक्ति के माध्यम से ही हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें शिक्षा के व्यावसायिक आदर्श को स्वीकार करना होगा। प्रबंधकीय व व्यावसायिक शिक्षा में ही ऐसी क्षमता है जो हमारे किशारों और युवाओं में वह शक्ति उत्पन्न कर सकेगी जिसके आधार पर वे भौतिकवादी सभ्यता के अनुकूल अपने को सबल और सक्षम बना सकेंगे तथा प्रतिद्वंदिता के लिए तैयार हो सकेंगे।

शनै:शनै सामाजिक परिवर्तन और विज्ञान में प्रगति के कारण व्यक्तियों की मानसिकता में परिवर्तन आया है और परम्परागत शिक्षा का स्थान प्रबंधकीय व व्यवसायिक शिक्षा ने ले लिया है। इसमें व्यक्तिगत कौशल के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, जिससे विद्यार्थी को अपने कौशल के आधार पर व्यवसाय की सुविधा उपलब्ध होगी। तकनीकी पाठ्यक्रमों की अधिकता होगी। विभिन्न प्रकार के प्रबंधकीय व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकास किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान के स्थान पर कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में बायोकेमिस्ट्री, लाईफ साइंस तथा

अधिक लंबे कोर्स के स्थान पर छोटे एवं डिप्लोमा कोर्स का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कम समय में ही विद्यार्थी के न केवल ज्ञान का विकास हो बल्कि उसके कौशल का भी विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शिक्षा या उपाधि, लक्ष्य नहीं है, वरन् एक साधन मात्र है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसी प्रकार उपाधि एवं व्यवसाय के मध्य भी गहन अंर्तसंबंध होता है। यह संबंध प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परस्पर तथा विलोम भी हो सकता है। वैदिक काल से शिक्षा की आरम्भिक स्थिति में केवल तीन विषयों का ही अध्ययन किया जाता था। ये थे गणित, भाषा और दर्शन। समय के साथ-साथ विभिन्न विषयों, उनमें विशेषज्ञता की मांग बढ़ते जाने के कारण विभिन्न प्रकार के विषय तथा संकाय बनते गए और उनमें लगातार वृद्धि होती रही। शिक्षा के प्रत्येक संकाय/क्षेत्र में उपाधि प्राप्त युवाओं की स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :-

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

दण्डारेख

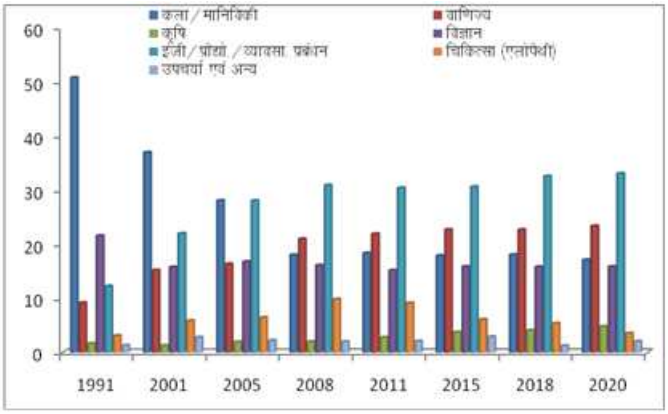

तालिका 1 एवं दण्डारेख के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1991 में जहां कला/मानिविकी क्षेत्र में उपाधि धारियों की संख्या 50.83 प्रतिशत थी वह क्रमबद्ध रूप से घटती हुई वर्ष 2020 में 17.31 प्रतिशत रह गई। जिसका मुख्य कारण कला/ मानिविकी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का कम होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार वाणिज्य के क्षेत्र में जहां वर्ष 1991 में 9.21 प्रतिशत डिग्री धारी थे, जो वर्ष 2020 आते-आते 23.42 प्रतिशत हो गये अर्थात् वाणिज्य के क्षेत्र में 14.21 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हो रही है। साथ ही कृषि के क्षेत्र में उपाधि धारियों की संख्या जहां वर्ष 1991 में 1.67 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 2020 में बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गयी है। इसका आशय यह है कि कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी के ज्ञान और कृषि क्षेत्र में अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कृषि के अध्ययन हेतु लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई। इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी व व्यावसायिक प्रबंधन के क्षेत्र में वर्ष 1991 में 12.28 प्रतिशत डिग्री धारी उपलब्ध थे, जबकि वर्ष 2020 में इनकी संख्या में आशातीत वृद्धि होते हुए 33.11 प्रतिशत हो गयी। इससे स्पष्ट होता है कि आई.टी. क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों ने लोगों को आकर्षित किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उपाधि धारियों की स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 1991 से वर्ष 2020 तक उपाधि धारियों की संख्या में घट-बढ़ देखा गया है। उपचर्या एवं अन्य उपाधि धारियों की स्थिति में भी वर्ष 1990 के बाद कुछ सुधार हुआ है।

मध्यप्रदेश में प्रबंधकीय शिक्षा में आये परिवर्तनों का अध्ययन - वर्तमान उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्विकरण के दौर में जहाँ एक ओर गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, वहीं दूसरी और जीवन एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को वर्तमान प्रबंधकीय संस्थाओं के लिये उपयुक्त बनाने के साथ-साथ उनके आत्मिक विकास के लिये नैतिक मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। जिसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से प्रबंधकीय शिक्षा में समय-समय पर परिवर्तन करती आ रही है। भारत में नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे यहाँ गुरूकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत धर्म ग्रंथों एवं नैतिक मूल्यों पर परिचर्चा आयोजित की जाती थी, जो विद्यार्थियों के नैतिक स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिसमें विदेशी विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक मात्रा में है। उच्च रोजगार दिलाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जीवन मूल्यों का संरक्षण करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उच्च शिक्षा क्षेत्र की है।

मानव विकास की जय-यात्रा में शिक्षा की भूमिका सर्वोपरि है। शिक्षा में प्रारंभ से ही विकासमूलक परिवर्तन हुए हैं और मनुष्य मात्र तक इसकी पहुँच हो सके इसके लिये इतिहास में प्रयोग भी होते ही रहे हैं। वर्तमान समय में आर्थिक और तकनीकी विकास के कारण होने वाले लाभों से समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने के लिये एक सुनियोजित और समन्वित प्रयास की जरूरत है।

उच्च शिक्षा का प्रायोजन व्यक्ति के जीवन में उच्च मूल्यों के विकास से जुड़ा है। इसके लिये अध्ययन-अध्यापन का प्रबंधन करने वाले सभी हितग्राहियों के समेकित प्रयास की जरूरत है। अकेले विद्यार्थी या प्राध्यापक अथवा अभिभावक के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिये समुचित दिशा-दर्शन की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिससे प्रेरित होकर एकांगी विकास की अवधारणा के विपरीत सामूहिक रूप से नैतिक विकास की नींव डाली जा सके। तेजी से बदल रही दुनिया के साथ ही शैक्षणिक जगत में भी परिवर्तन की लहर है। नयी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में नये संस्थान खोले गये हैं जिनमें और नित नये पाठ्यक्रमों की माँग भी बढ़ रही है। आवश्यकता इस बात की भी है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये संधारणीय विकास के साथ-साथ हमारी चेतना में गुणात्मक विकास भी संभव हो सके।

मध्यप्रदेश में प्रबंधकीय शिक्षा में परिवर्तन प्रमुख रूप से वर्ष 1990 के पश्चात् देखा गया है। इसके पूर्व प्रदेश में मात्र 4-5 विश्वविद्यालय संचालित थे जहां बी.बी.ए. एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रय संचालित किए जाते थे। जिनमें जीवाजी विश्वविद्यालय, इंदौर, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ग्वालियर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर एवं डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर तथा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल प्रमुख थे। किन्तु वर्ष 1990 के पश्चात् प्रबंधकीय शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2022 तक प्रबंधकीय शिक्षा से संबंधित 50 शासकीय व निजी क्षेत्र की महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए। प्रबंधकीय शिक्षा में आये परिवर्तनों को योजनाकाल के दौरान उच्च शिक्षा के विकास के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

राज्यवार स्थिति के अवलोकन उपरांत मध्यप्रदेश के जिलों में संचालित प्रबंधकीय शिक्षा से जुड़े संस्थानों का अध्ययन निम्न तालिका में किया

गया है।

तालिका क्रं. 2: मध्यप्रदेश में प्रबंधकीय शिक्षा संस्थानों की स्थिति (जिलावार)

क्रं.	जिले का नाम	प्रबंधकीय शिक्षा संस्थानों की संख्या
1.	भोपाल	18
2.	इंदौर	10
3.	ग्वालियर	10
4.	जबलपुर	06
5.	उज्जैन	06
6.	छिंदवाड़ा	04
7.	रीवा	04
8.	सागर	03
9.	सतना	03
10.	मंदसौर	02
11.	नीमच	02
12.	सिहोर	02
13	बालाघाट	01
14.	बड़वानी	01
15.	भिण्ड	01
16.	छतरपुर	01
17.	डिंडोरी	01
18.	हरदा	01
19.	कटनी	01
20.	नरसिंहपुर	01
21.	रतलाम	01
22.	शहडोल	02
23.	शाजापुर	01
24.	श्योपुर	01
25.	होशंगाबाद	03
26.	बीना	02
27.	बैतूल	02
	योग	33

स्रोत:-https://bschool.careers360.com/colleges.

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान मध्यप्रदेश के 55 जिलों में से 27 जिलों में प्रबंधकीय शिक्षा के अंतर्गत बी.बी.ए. व एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित हैं। जिनमें से सबसे अधिक संख्या भोपाल में 18, इंदौर में 13, ग्वालियर में 10, जबलपुर में 06, छिंदवाड़ा में 03, रीवा में 04, सागर में 03, सतना में 03, मंदसौर, नीमच, सिहोर, शहडोल, बीना, बैतूल में 02-02 तथा अन्य जिलों में 01-01 संस्था संचालित है। इस प्रकार देखा जाये तो अभी भी 28 ऐसे जिले हैं जहां प्रबंधकीय शिक्षा संस्थान संचालित नहीं है अथवा विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण बंद हो चुके हैं।

प्रदेश के 90 प्रबंधकीय संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया में पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में काफी परिवर्तन हुआ है। पूर्व में प्रबंधकीय शिक्षा में प्रवेश हेतु कोई पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती थी, केवल स्नातक के अंकों के आधार पर गुणानुक्रम सूची तैयार कर विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया जाता था, किन्तु वर्तमान में प्रबंधन के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने हेतु स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिए नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा Common Management Admission Test, (CMAT), Management Aptitude Test (MAT), Common Admission Test (CAT) आदि प्रारम्भिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रारम्भिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मेरिट अंकों के आधार पर संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।

2011 तक, भारत में प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए कई प्रवेश परीक्षाएँ थीं। इनमें CAT, JMET XAT, Gitam, SAT, NMAT, SNAP, MAT, राज्य-विशिष्ट परीक्षाएँ, चइअ संस्थानों के प्रबंधन संघों द्वारा आयोजित परीक्षाएँ और निजी कॉलेजों द्वारा आयोजित परीक्षाएँ शामिल थीं। AICTE (All India Council for Technichal Education) ने कई परीक्षाओं में भाग लेने के लिए छात्रों के बोझ (शारीरिक, मानसिक और वित्तीय तनाव) को कम करने के लिए CMAT की शुरुआत की।

वर्ष 2015 तक सीमैट का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता था, लेकिन एआईसीटीई ने यह परीक्षा वर्ष में एक बार जनवरी के तीसरे रविवार को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

इन प्रारम्भिक परीक्षाओं में देश, प्रदेश के नहीं अपितु विदेशों में रहने वाले छात्र/छात्रायें भी सहभागिता करते हैं। मध्यप्रदेश के लाखों की संख्या में विद्यार्थी इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं जबकि मध्यप्रदेश में प्रबंधकीय शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्या लगभग 22000 है। वर्तमान में प्रबंधकीय शिक्षा की मांग को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता है कि इन संस्थानों में प्रवेश हेतु सीट संख्या में वृद्धि की जाये ताकि विद्यार्थियों को प्रबंधकीय शिक्षा स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष - निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि उपाधि तथा व्यवसाय के मध्य संबंध मांग तथा पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित रहा है। पूर्ति की प्रक्रिया में लगने वाला समय तथा मांग में असमय होने वाले परिवर्तन इन क्षेत्रों में बेरोजगारी के रूप में सामने आते हैं। उपाधि प्राप्त करने का प्राथमिक दृष्टिकोण पूर्व में व्यवसाय या नौकरी प्राप्त करना ही रहा है। लगभग 25 वर्ष पूर्व तक यह स्थिति थी कि कोई भी उपाधिधारी व्यक्ति स्वत: ही रोजगार प्राप्त कर लेता था। परन्तु अब मात्र उपाधि धारक होने से वह नौकरी के योग्य नहीं बन जाता है। व्यक्ति में डिग्री के अतिरिक्त अन्य योग्यताएँ विकसित होने की आवश्यकता होती है। समय के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की आवश्यकता अनुभव की गई तथा उनकी मांग की पूर्ति के लिए भी विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम या उपाधियाँ प्रदान की जाने लगीं, जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति तुरंत नौकरी पाने के योगय हो जाता था। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक कुशलताओं से भरे पाठ्यक्रमों के द्वारा व्यक्तियों की पूर्ति ने भी अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न की है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देश में जहां रोजगार के अवसर कम तथा जनसंख्या की अधिकता के कारण इनके मध्य संबंध सीधा न दिखाई देकर विकृत रूप में सामने आया है।

यद्यपि भारत एवं प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में काफी आमूलचूल बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं। विद्यार्थियों को इस नीति के तहत अपने पसंद के पाठ्यक्रमों का चयन कर अपनी दक्षता में वृद्धि करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। एक डिग्री के साथ अन्य डिप्लोमा कोर्स करने का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही स्थानीय परिवेश के आधार पर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम

(Vocational Course) को शामिल किया गया है जिससे विद्यार्थी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा प्राप्त कर रोजगार के अवसर तलाश कर सके। उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024 में आई.आई.टी. नई दिल्ली से ए.आई. एवं ए.आई. विथ फिनटेक जैसे महत्वपूर्ण व कौशलबर्द्धक सर्टिफिकेट कोर्सों को नि:शुल्क संचालित किया है। मध्यप्रदेश में उक्त कोर्सों को वर्तमान में केवल प्रत्येक जिले के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालयों (अग्रणी) एवं स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की इस सराहनीय पहल से न केवल आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों से शिक्षा प्राप्त करेंगे बल्कि आई.टी. क्षेत्र में अपने कौशल में वृद्धि कर आत्मनिर्भर बनेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Nehru, Pt. Jawaharlal, "The Discovery of India", Pg. 351.
2. Pathak P.D., "Problem in Indian Education", Agrwal Publication, Agra, 2006.
3. तकवाले, प्रो. राम, भारत के उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण की चुनौतियां एवं सम्भावना, गोल्डन लेक्चर सीरीज, यू.जी.सी., वर्ष 2015।
4. आचार्य रजनीश, शिक्षा में क्रांति, पृ. 13।
5. सिंह, डॉ. जे.डी., भारत में वर्तमान शिक्षा की स्थिति व चुनौतियां, इंटरनेशनल एजुकेशन जर्नल, ISSN- 2455-8729, चेतना प्रकाशन, 19 जुलाई 2017, पृ. 88।
6. मुखोपाध्याय, श्रीधरनाथ, भारतीय शिक्षा का इतिहास, पृ. 196-199।
7. श्रीवास्तव, शंकरशरण, शिक्षा और स्वतंत्रता, भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, लखनऊ, 2007।
8. सेन, प्रो. अमर्त्य सेन, Poverty in Underdeveloped Economy, वर्ष 1998।
9. Thakur D. Vocational & Technical Education, Edited, Deep & Deep Publication. New Delhi, 1996.

तालिका 1: शिक्षा के प्रत्येक संकाय/क्षेत्र में उपाधिधारियों की स्थिति

(संख्या प्रतिशत में)

क्रं.	विषय/क्षेत्र	उपाधिधारियों की वर्षवार स्थिति							
		1991	2001	2005	2008	2011	2015	2018	2020
1.	कला/मानिविकी	50.83	37.01	28.11	18.05	18.39	17.93	18.1	17.13
2.	वाणिज्य	9.21	15.21	16.37	21.01	21.95	22.74	22.71	23.42
3.	कृषि	1.67	1.27	1.94	2.00	2.78	3.78	4.1	4.82
4.	विज्ञान	21.6	15.8	16.78	16.14	15.19	15.88	15.82	15.89
5.	इंजी/प्रौद्यो./व्यावसा. प्रबंधन	12.28	22.01	28.09	30.95	30.43	30.64	32.61	33.11
6.	चिकित्सा (एलोपैथी)	3.12	5.9	6.46	9.85	9.16	6.11	5.41	3.56
7.	उपचर्या एवं अन्य	1.29	2.80	2.25	2.00	2.10	2.92	1.25	2.07

स्रोत :- आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022।

****